RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-04
April -2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]

भारत–अमेरिका संबंधः 123 असैन्य परमाणु समझौते के संदर्भ में

प्रवेश कुमार

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 16 Apr 2020

Keywords
असैन्य, परमाणु, रिएक्टर, तकनीकी, फास्ट ब्रीडर, महाशक्ति, सामरिक।

ABSTRACT

123 भारत–अमेरिकी असैन्य परमाणु समझौता 2007 के 40 पृष्ठों के दस्तावेज को समझने से पूर्व इस पहलू पर गौर करना आवश्यक है कि भारत के विरूद्ध इस समझौते में ऐसा कोई तत्व न हो, जिसके जरिए अमेरिकी सहयोग से बने तारापुर रिएक्टर को ईंधन आपूर्ति बंद करने जैसी घटना दोहराई जाए। दूसरा, भारत को किसी भी सूरत में भविष्य में सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से परमाणु परीक्षण करने के अपने अधिकार को नहीं छोड़ना चाहिए। अंततः भारत को अपने परमाणु हथियार को अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी के लिए नहीं खोलना चाहिए। भारतीय नागरिक एवं वैज्ञानिक इस परमाणु सौदे को इन तीन बातों के आधार पर देख रहे थे और उन्होंने यह महसूस किया कि इससे भरत का घरेलू परमाणु कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा।

शोध विस्तार– अमेरिका के साथ परमाणु मुद्दे पर सहयोग मिलने से भारत की तकनीक संबंधी बहुत सी मुश्किलें दूर होगी और विकास की गति में भी तेजी आएगी। चूंकि देश की ऊर्जासुरक्षा योजना में परमाणु ऊर्जा का अहम स्थान है, इसलिए अमेरिका के साथ किए गए समझौते से पश्चिमी देशों में भारत के प्रति मौजूद शक और शंका को दूर करने में भी मदद मिलेगी। इसी तरह अमेरिका भारत की तकनीकी क्षमताओं को समझता है।[1] जब सुपर कम्प्यूटर की बिक्री को उसने नकार दिया गया था, तो भारत ने कुछ समय बाद खुद एक सुपर कम्प्यूटर बनाया और इसे अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में शामिल किया। इतिहास उलटकर देखे तो यह बात सामने आती है कि अमेरिका की नजर में भारत ने स्वयं को एक प्रबल ताकत के रूप में कभी प्रोजेक्ट नहीं किया है। ताकतवर देश का दर्जा मिलने के बाद भारत ने हमेशा वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए प्रयास किया है।[2]

लेकिन अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि अगर भविष्य में भारत परमाणु परीक्षण करता है तो क्या तारापुर ईंधन की आपूर्ति करने से मना कर सकता है ? इसका सैद्धांतिक तौर पर जवाब होगा हां। लेकिन सच्चाई यह है कि इस तरह का सख्त कदम उठाने से पहले उसे कई चरणों से गुजरना होगा। समझौते के अनुसार सबसे पहले अमेरिका को इस बात की जांच करनी होगी कि अगर परमाणु परीक्षण बदलते भू–राजनीतिक माहौल में किया गया है, तो अमेरिका को किसी तरह की आपत्ति नहीं होगी। इस संदर्भ में परमाणु कार्यक्रम के लिए आपूर्ति किए गए ईंधन का पुनर्प्रसंस्करण भी जारी रहेगा। बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत को भविष्य में परमाणु परीक्षण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर इसकी जरूरत पड़ती भी है तो इसे प्रयोगशाला में किया जा सकता है।

जब भारत और अमेरिका के बीच वार्ता शुरू हुई तो इस्लामाबाद ने अमेरिका से गुहार लगाई कि वह इसी तरह का समझौता पाकिस्तान से भी करे। अमेरिका ने उसकी अपील यह कहते हुए साफ नकार दी कि पाकिस्तान गुप्त तौर पर इस्लामिक जगत, विशेषकर ईरान और लीबिया को परमाणु हथियार की तकनीक देने का दोषी है। अमेरिका ने यह भी कहा कि परमाणु मुद्दे पर पाकिस्तान भरत के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकता। अगले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया में भरत अमेरिका असैन्य परमाणु सहयोग समझौते की बारीकियों को समझने के लिए बहस होगी।[3]

123 समझौते के सम्पूर्ण ब्यौरे से साफ होता है कि इस बहुचर्चित समझौता में भारत ने कुछ खोया नहीं बल्कि पाया ही है। समझौते के तुरन्त पश्चात् भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने तात्कालिक शंकाओं को दूर करते हुए संसद में समझौते को लेकर देश को स्पष्ट रूप से भरोसा दिलाया कि यह समझौता देश हित में है। प्रारम्भ में देश में यह आशंका जताई जा रही थी कि वाशिंगठन में संधि के बाद भारत को परमाणु हथियार कार्यक्रम बंद करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कई संदेहों को दूर किया तथा देश को आश्वस्त किया कि सामरिक परमाणु कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अमेरिका व अन्य स्रोतों से इंधन सप्लाई सुनिश्चित रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ऐजेंसी की निगरानी के दायरे में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नहीं आएंगे। वाई इन शर्तों के साथ भारतीय परमाणु कार्यक्रम की स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आने वाली है।

परमाणु समझौते का विरोध देश के बाहर व भीतर दोनों ओर देखने को मिला, इस दौरान अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ऐजेंसी (IAEA) के तत्कालीन अध्यक्ष अल बरदेई की भारत यात्रा भी महत्वपूर्ण रहीं। अपनी गैर राजनीतिक हैसियत और पद की गरिमा का पूरा–पूरा ख्याल रखते हुए अदबरदेई

RRIJM 2015, All Rights Reserved

ने परमाणु मामले पर सार्वजनिक रूप से भारत के हित में ही वक्तव्य दिया एवं अपना विश्वास भारत की नीति में व्यक्त किया। उन्होंने भारत के अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ऐजेंसी के साथ अतीत में हुए चार सेफगार्ड एग्रीमेंट पर टिप्पणी करते हुए इसे आदर्श प्रक्रिया का दर्जा दिया।[4]

इससे समझा जा सकता था कि 123 समझौते के तहत परमाणु ऊर्जा ऐजेंसी और भारत के बीच सौदेबाजी को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के बीच में कोई बड़ी बाधा शेष नहीं बची थी लेकिन परमाणु समझौता को लेकर यहां की अंदरूनी राजनीति की गर्माहट को देखते हुए बरदेई ने तत्काल कहा जब वे (भारत सरकार) तैयार होंगे, तभी हम उनसे समझौता कर लेंगे अभी इस विष पर राजनीतिक संवाद चल रहे है।

जहां तक परमाणु ऊर्जा ऐजेंसी प्रमुख बरदेई का सवाल है, वे उन प्रमुख लोगों में से थे, जिन्होंने जुलाई 2005 केइस समझौते की जोरदार ढंग से पैरवी की थी। भरत के पक्ष में उनके समर्थन का कारण बिल्कुल स्पष्ट भी था। 1975 में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण के बाद 34 से ज्यादा वर्षों से भारत विश्व परमाणु बिरादरी द्वारा प्रताड़ित होता रहा है और अब इस बिरादरी में उसकी वापसी में सभी का हित है। अल बरदेई ने दिल्ली में कहा 'मैं चाहता हूं कि भारत परमाणु क्षेत्र में हर तरह से पूर्ण भागीदार बने' इसके पास अच्छी तरह विकसित अपना घरेलू परमाणु क्षेत्र है, यह परमाणु तकनीक के आपूर्तिकर्ता और ग्रहक दोनों की भूमिका निभा सकने का सामर्थ्य रखता है। भारत का एक दोस्त होने के नाते मैं उसे परमाणु ऊर्जा का भरपुर दोहन करते हुए देखना चाहता हूं ताकि वह अपनी 10 प्रतिशत की विकास दर को बरसमझौता रख सके।[5]

वैश्विक परमाणु बिरादरी तथा इक्कीसवीं सदी की हाईटेक पंचायत में प्रवेश की दिशा में जुलाई 2005 के समझौते को क्या हासिल हुआ, यह पूर्वाग्रह रहित वस्तुनिष्ठ आंकलन का विषय है। हमें परमाणु बिरादरी में भारत की इस असामान्य हैसियत के मूल्य को समझना चाहिए। यह कहना गलत है कि इसका प्रभाव भारत की संप्रभुता और उसकी सुरक्षा पर किसी भी तरह से पड़ेगा। लेकिन आज का यथार्थ यह है कि परमाणु समझौता को लेकर भारत की घरेलू राजनीतिक बहस इस मुकाम तक पहुंच चुकी है कि भारत और अमेरिकी नेतृत्व वाले शेष विश्व के बीच में रिश्तों की प्रकृति क्या होनी चाहिए, इस मुद्दे पर जनमत का ध्रुवीकरण भी समझौते के पक्ष में साफ नजर आने लगा। पिछले 34 वर्ष से परमाणु मामलों में अलग–अलग रहे भारत के लिए इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता था, समय पर सही निर्णय कर इस मौके का फायदा उठाना निश्चित ही भारत के लिए लाभप्रद रहा।[6]

भारत अमेरिकी 123 परमाणु समझौते के लाभ हानि एक विश्व राजनीति पर पडने वाले प्रभावों को समझने से पूर्व भारतीय राजनीति में इस समझौते को लेकर उठे विवादों की व्याख्या भी प्रासंगिक होगी। परमाणु समझौते की लम्बी प्रक्रिया के दौरान देश में संद के अन्दर व बाहर विरोधियों का खूब शोरगुल रहा। अगर विरोधियों का मान भारत समझौते से पीछे हटता तो ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की विधिसम्मत चुनी गई सरकार की साख का गहरा आघात लगता। एक लोकतंत्र के तौर पर हम अपनी कमजोरियों को समझते है, लेकिन हम एक ऐसे देश है जिसने पिछले छह दशक में पर्याप्त लचीलापन दर्शाया है। जो सत्तोन्मुखी प्रशासन, राजनीतिक अस्थिरताओं और पुरातनपंथी विचारधारा से चलने वाली राजनीति के सागर में लोगों की दृढ़ इच्छाशक्ति और महत्वाकांक्षाओं के द्वीप के रूप में मजबूती से जमा है।

आखिरकार, हमने इस परमाणु समझौता पर तीन वर्षों तक निरन्तर वार्ता की है, जिसके दौरान इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और दूसरे कई लोगों ने इस समझौता के फायदे नुकसान और लेन–देन का विशद विश्लेषण किया। साफ था कि पीछे हटने से सीमापार देशों में भारत की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ता और देश के भीतर भी सरकार के प्रति जनता के भरोसे में कमी आती। वैसे भी हमारे आलोचक मानते है भारत की निर्णय क्षमता कमजोर है। समझौते से पीछे हटने से उनकी इस धारणा को और बल मिलता।[7]

भारत यह समझौता दुनिया की उस एकमात्र महाशक्ति के साथ करने जा रहा था, जो एक सिर्फ अपनी विदेश और सुरक्षा नीति में बदलाव के लिए तैयार हो गयी थी वरन उसने हमारी सामरिक हथियारों की क्षमता को स्वीकारते हुए (जिसे वह पिछले साढ़े तीन दशक तक रोकने की कोशिश करता रहा) तथा हमारे विकास के लिए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी हेतु रास्ता साफ करने के लिए अपने कानूनों में संशोधन की मंशा भी जताई। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वह भी भारत को एक 'जिम्मेदार देश' मानता है। यदि हम तयशुदा समझौते से अपने कदम वापस खींचते है तो नई दिल्ली आगे और कब तक ऐसा होने का दावा कर सकती थी ?

इस परमाणु सहयोग समझौते को अमल में लाने व क्रियान्वित करने में असफल रहने पर सबसे ज्यादा नुकसान यह होता कि हमारी ऊर्जा संबंधी कमी भविष्य में और बढ़ जाए, जिससे हमारे आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस कमी की भरपाई के किसी भी प्रयास के तहत थर्मल पावर पर, इसके पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को जानने के बावजूद हमारी निर्भरता बढ़ जाएगी और पेट्रोलियम आयात के लिए हमें अशांत खाड़ी क्षेत्र की ओर ताकना पड़ेगा। साथ ही कोयले की जरूरत भी और बढ़ जाएगी।[8]

RRIJM 2015, All Rights Reserved

इसके साथ हमारी परमाणु सहयोग समझौते के क्रियान्वयन में असफलता को अमेरिका और दूसरे औद्योगिक देशों में बैठे परमाणु अप्रसार के स्वयं भू–आका अपनी बहुत बड़ी जीत मानते, जो शुरूआत से ही इस संधि का विरोध कर रहे थे। इससे कम से कम इतना नुकसान तो अवश्य होता कि भारत का आकर्षण अमेरिका के लिहाज से काफी घट जाता और उसकी नजर मं हम एक 'जिम्मेदार राष्ट्र' नहीं रह पाते, क्योंकि हमारा चयनित नेतृत्व तीन साल तक सख्त मोल तोल करने के बाद पीछे हट जाता। वैश्विक राजनीति की प्रकृति को देखते हुए इस बात का भी खतरा उत्पन्न हो जाता कि दुनिया में भारत के परमाणु शक्ति सम्पन्न होने की 'स्वीकार्यता' इस समझौते के आधार पर बिना समर्थन खोने लगती इन परिस्थितियों में ऐसी उम्मीद करना गेर वाजिब नहीं है कि भले ही हम अपने परमाणु शक्ति संपन्नता को तिलांजलि न दे, लेकिन इसे आगे न बढ़ाने का दबाव बढ़ जाता यह मांग बनी रह सकती है कि हम भविष्य में परमाणु परीक्षण न करे।[9]

इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस समझौते को अस्वीकार करने से दुनिया में यही संदेश जाता कि भारत चीन के साथ मिलकर नए स्तरों पर सामरिक साझेदारी करना चाहता है। अतीत में भी अमेरिका और इसकी दादागिरी के खिलाफ चीन–भारत–रूस का त्रिकोणीय गठजोड़ बनाने की बाते हवा में तैरती रही है। यहां तक कि इससे देश के हित शायद ही सधें ओर यह हमें इच्छा या अनिच्छा से दुनिया के बढ़ते ध्रुवीकरण में धकेलकर हमारी विदेश नीति के विकल्पों को सीमित कर सकता है। इस समझौते को इसकी तार्किक परिणति तक ले जाने में असफल रहने से भारत अमेरिकी साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ता है।[10]

इस स्तर पर हम यहीं कर सकते है कि 123 परमाणु समझौते के कुछ बिन्दुओं, जिनके बारे में एकराय नहीं है, पर और विचार करें, विशेषकर तब जबकि दोनों देशों की इनमें इतनी ज्यादाराजनीतिक पूंजी लगी है। समझौता किसी भी निर्णय का अनिवार्य घटक है, किसी व्यक्ति के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। जरूरी यह नहीं कि समझौता किया गया बल्कि यह देखना जरूरी है कि समझौता अच्छा है या बुरा। और यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि 123 परमाणु समझौता अच्छे की श्रेणी में ही आता है।[11] वर्ष 2008 में 2 अक्टूबर 2008 गुरूवार सुबह 6:19 बजे शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्रि के मौके पर भारत को परमाणु शक्ति के क्षेत्र में अहम कामयाबी मिली जब तीन वर्ष तक काफी उतार–चढ़ाव देखने के बाद अंततः वह ऐतिहासिक क्षण आया जब भारत के साथ 123 परमाणु समझौता पर अमेरिकी सीनेट ने कई विवादों का पटाक्षेप कर समझौते के पक्ष में 86 (13 मत विरोध में) मत दे उसे मंजूरी दे दी, इसी के साथ यह साबित हो गया कि भारत को विश्व ने परमाणु शक्ति मान लिया है और कोई भी उसकी अनदेखी नहीं कर सकता है। इससे पूर्व अमेरिका के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने 298–117 के बहुमत से समझौते को स्वीकृति दे दी थी। व्हाइट हाऊस में बुश के दस्तखत के बाद 11 अक्टूबर 2008 को अमेरिकी विदेश मंत्री कोडोलिजा राइस एवं भारतीय विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने समझौते पर अंतिम रूप से दस्तखत कर इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त कर दिया।[12]

यहां उल्लेखनीय है कि अमेरिका से हुए परमाणु समझौते से ठीक दो दिन पहले अर्थात 30 सितम्बर 2008 को भारत और फ्रांस के बीच बसैन्य परमाणु सहयोग का समझौता हुआ था।[13] समझौतों से निश्चित ही भारत को आर्थिक एवं राजनीतिक लाभ मिलने वाला है सन् 2030 तक भारत में 30 से 60 हजार मेगावाट परमाणु ऊर्जा पैदा करने की क्षमता विकसित होगी एवं सन् 2030 तक 150 अरब डॉलर के नये निवेश की संभावनाऐ भी भारत में होने की संभावनाऐं बनेगी। ऐसे ही समझौते भारत इसके पश्चात कनाडा, रूस, कजाकिस्तान, वेनेजुएला आदि देशों से कर चुका है एवं फलस्वरूप पोकरण परमाणु परीक्षणों के बाद भारत के खिलाफ लागू प्रौद्योगिकी निषेध व्यवस्था निर्णायक तौर पर लुप्त हो गयी है। इन समझौतों का तत्काल लाभ सामने आने लगे है अब भारत के परमाणु रिएक्टरों को पर्याप्त यूरेनियम की आपूर्ति होने लगी है जो रिएक्टर 40 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रहे थे वे अपनी क्षमता बढ़ाने में सफल हो गये है, भारत, कनाडा, और कजाकिस्तान से यूरेनियम आयात के समझौते कर रहा है। आगे चलकर भारत स्वयं भी परमाणु आपूर्तिकर्ता राष्ट्र बन सकता है एवं समूह–8 (जी–8) का सदस्य बनने की अपनी दावेदारी को मजबूती से रख सकता है।[14]

निष्कर्षः– अमेरिका वर्तमान विश्व परिदृश्य में भारत को पाकिस्तान से ज्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्र मान रहा है, क्योंकि दक्षिण एशिया में चीन अमेरिका में निरन्तर दूरियॉ बढ़ रही है। इन परिस्थितियों में वह चीन के विरूद्ध भारत जैसे परमाणु शक्ति सम्पन्न जिम्मेदार राष्ट्र की परम आवश्यकता महसूस करता है। वहीं भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरतों तथा यूरेनियम की निर्बाध आपूर्ति हेतु अमेरिका से प्रगाढ़ संबंध एक विकल्प के रूप में देखता है। अतः वर्तमान भारत– अमेरिका परमाणु संबंधों में बना सकारात्मक दृष्टिकोण निश्चित ही अध्ययन का व्यापक एवं महत्वपूर्ण विषय है।

संदर्भ सूचीः–

1. द हिन्दु, नई दिल्ली, 23 अक्टूबर 1996
2. द टाईम्स ऑफ इण्डिया, 11 सितम्बर, 2007
3. द वीक, 2 सितम्बर, 2007
4. द इण्डियन एक्सप्रेस, 8 मार्च, 2006
5. फ्रन्टलाईन, नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2007
6. द वीक, अक्टूबर 2008
7. दैनिक जागरण, नई दिल्ली, 12 अक्टूबर 2007
8. दैनिक भास्कर, जयपुर 13 अक्टूबर 2007
9. द टाईम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2007

RRIJM 2015, All Rights Reserved

10. जसजीत सिंहः समझौता से पीछे हटने का मतलब, दैनिक भास्कर, जयपुर 23 अगस्त, 2007
11. दैनिक भास्कर, जयपुर 3 अक्टूबर 2008
12. न्यूयार्क टाईम्स, 30 सितम्बर, 2008
13. हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2008
14. द इण्डियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2008

RRIJM 2015, All Rights Reserved